भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 91

दिनांक 20 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

मराठवाड़ा में जल की कमी और उसका उपशमन

91. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा सुपर अल नीनो मौसमी गड़बड़ी की वजह से तेज़ी से कम हो रहे भूजल की समस्या से निपटने के लिए मराठवाड़ा और मध्य भारत में जिला-वार जलवैज्ञानिक मूल्यांकन करवाया है;

(ख) सूखा-प्रवण खंडों में जलवायु-अनुकूल सूक्ष्म-सिचाई संरचनाओं के निर्माण हेतु अटल भूजल योजना और राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति तथा इनके अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए निर्धारित वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सूखा-संभावित छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) और जालना जिलों के लिए एक विशेष औद्योगिक और ग्रामीण जल ग्रिड को मंजूरी देने की योजना बना रही है, ताकि बिडकिन (एयूआरआईसी) जैसे बढ़ते औद्योगिक केंद्रों और स्थानीय ग्रामीण आबादी दोनों के लिए लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भूजल पुनर्भरण, निष्कर्षण, उपलब्धता और भूजल निष्कर्षण के चरण में परिवर्तन का आकलन करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) राज्य सरकारों के समन्वय से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश भर में आवधिक सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन करता है। सक्रिय भूजल संसाधन मूल्यांकन, 2025 के अनुसार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण क्रमशः 33.89 बीसीएम, 14.30 बीसीएम और 36.07 बीसीएम आंका गया है। संबंधित वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन क्रमशः 31.99 बीसीएम, 13.07 बीसीएम और 34.15 बीसीएम अनुमानित किए गए हैं, जबकि वार्षिक भूजल निकर्षण क्रमशः 16.57 बीसीएम, 6.30 बीसीएम और 20.26 बीसीएम आंकी गई है। तदनुसार, भूजल निष्कर्षण का चरण महाराष्ट्र में 51.79 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 48.18 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 59.32 प्रतिशत आंका गया है।

(ख): अटल भूजल योजना को महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2020-21 से अक्टूबर 2025 तक 1,133 ग्राम पंचायतों के 1,442 गांवों में 965.15 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ लागू किया गया था। यह योजना दिनांक 15.10.2025 को समाप्त हो गई है। इस योजना में राज्य के 13 जिलों के 43 जल की कमी वाले ब्लॉकों को शामिल किया गया था। वर्ष 2023-2025 के दौरान किए गए आवधिक आकलन से कवर किए गए 43 ब्लॉकों में से 39 में भूजल स्तर में सुधार का संकेत मिलता है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) को वर्ष 2016-2024 के दौरान कार्यान्वित किया गया था और बाद में इसे सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। तब से यह परियोजना भौतिक और वित्तीय रूप से बंद हो गई है। महाराष्ट्र में, टेलीमेट्री के साथ 351 डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) की खरीद और स्थापना, राज्य डेटा केंद्र की स्थापना और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के विकास सहित सभी अनुमोदित परियोजना गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की लागत 27.00 करोड़ रुपये थी।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन करने के लिए, भारत सरकार जल शक्ति अभियान (जेएसए), जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी), जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल, मिशन अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के विभिन्न घटकों, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) जैसी विभिन्न चल रही योजनाओं के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि भूजल पर निर्भरता कम करने और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार करने सहित जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र के 11 प्रमुख बांधों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जल के अंतरण को सुगम बनाया जा सके।

*****